RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 277
दि. 08.02.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता नई दिशा में रणनीतिक रिश्ते

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। यह समझौता ऐसे समय में सामने आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों और संरक्षणवादी नीतियों के दबाव से गुजर रही है। इस पृष्ठभूमि में अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए कुल टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना न केवल भारत के लिए बड़ी राहत है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि वाशिंगटन अब नई दिल्ली को एक दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे 'बड़ी खबर' बताए जाने के पीछे यही सोच निहित है कि यह फैसला भारतीय उद्योग, निर्यातकों और रोजगार बाजार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। समझौते का सबसे अहम पहलू यह है कि इससे भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिका का लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर का विशाल उपभोक्ता बाजार और अधिक सुलभ हो जाएगा। विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए यह एक बड़ा अवसर है, जो लंबे समय से उच्च टैरिफ और गैर-शुल्क बाधाओं के कारण अमेरिकी बाजार में अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। कपड़ा, चमड़ा, रत्न-आभूषण, हस्तशिल्प और फार्मास्युटिकल्स जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में लागत कम होने से भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। इसका सीधा असर उत्पादन बढ़ने, निर्यात ऑर्डर में इजाफा होने और देश के भीतर रोजगार सृजन पर पड़ेगा, खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए, जिनकी भागीदारी इन क्षेत्रों में पहले से अधिक है।

यह समझौता केवल टैरिफ कटौती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक और कूटनीतिक निहितार्थ भी गहरे हैं। पिछले वर्ष अगस्त में भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाया था, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस अतिरिक्त

शुल्क को हटाने का फैसला यह दर्शाता है कि दोनों देश व्यावहारिक समझौतों के जरिए मतभेदों को सुलझाने के पक्ष में हैं। भारत की ओर से रूस से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से तेल आयात बंद करने और अमेरिका से ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाने की प्रतिबद्धता ने इस रास्ते को आसान बनाया है। इससे न केवल व्यापारिक संबंध सुधरेंगे, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग को भी नई मजबूती मिलेगी।

कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर भारत ने इस समझौते में संतुलित रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है। मक्का, गेहूं, चावल, पोल्ट्री और डेयरी उत्पादों को सुरक्षित श्रेणी में रखते हुए इन पर अमेरिकी आयात की अनुमति नहीं दी गई है। यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों की आजीविका की रक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर, अमेरिका द्वारा भारतीय मसालों, चाय, कॉफी और फलों को जीरो-ड्यूटी पर अपने बाजार में प्रवेश देने से भारतीय कृषि निर्यात को नई गति मिलेगी। इससे मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। समझौते के तहत भारत द्वारा अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, विमान, विमान के पुर्जे और उच्च तकनीक वाले उपकरण खरीदने की योजना दोनों देशों के औद्योगिक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। इससे भारत की एविएशन, रक्षा और उन्नत विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती मिलेगी, जबकि अमेरिका को एक स्थिर और बड़े खरीदार के रूप में भारत का साथ मिलेगा। बदले में, अमेरिका द्वारा भारतीय जेनेरिक दवाओं और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ में दी जाने वाली विशेष छूट भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा करेगी, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता की जरूरत महसूस की जा रही है। इस व्यापारिक ढांचे का एक और महत्वपूर्ण आयाम भविष्य की तकनीकों में सहयोग है। दोनों देशों के बीच डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर सहमति बनना इस बात का संकेत है कि भारत और अमेरिका केवल पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि ज्ञान-आधारित और तकनीक-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर मिलकर बढ़ना चाहते हैं। इससे भारत को वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में अधिक मजबूत स्थान मिल सकता है और घरेलू नवाचार को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका पहले से ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। वर्ष 2021 से 2025 के बीच भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 18 प्रतिशत रही है, जबकि आयात में यह 6 प्रतिशत से अधिक रही। द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिका का हिस्सा 10 प्रतिशत से ज्यादा है, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 186 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें भारत का निर्यात आयात की तुलना में अधिक रहा। नए समझौते के बाद इन आंकड़ों में और वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर यह अंतरिम व्यापार समझौता केवल आर्थिक लाभ का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत-अमेरिका संबंधों में विश्वास, रणनीतिक साझेदारी और दीर्घकालिक सहयोग का प्रतीक है। वैश्विक मंच पर बदलते शक्ति संतुलन के बीच दोनों देश एक-दूसरे के पूरक के रूप में उभर रहे हैं। यदि यह समझौता तय समय पर औपचारिक रूप ले लेता है और इसकी शर्तों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका का आर्थिक रिश्ता न केवल मजबूत होगा, बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भी एक स्थिर और भरोसेमंद मॉडल के रूप में सामने आ सकता है।

हिमाचल में आपराधिक मामलों पर सियासी बहस फिर तेज

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है, जिसमें राज्य के सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज 45 आपराधिक मामलों को वापस लेने की अनुमति मांगी गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च 2026 तय कर दी है। यह याचिका हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 26 अप्रैल 2024 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार को सभी मामलों को वापस लेने की इजाजत नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और सत्ता तथा विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं।

यह मामला सुक्खू सरकार के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश के वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ दर्ज कुल 65 आपराधिक मामलों को वापस लेने की सिफारिश की थी। सरकार का तर्क था कि इनमें से अधिकांश मामले राजनीतिक प्रकृति के हैं और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में, खासकर कोविड महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के बीच रैलियां और विरोध प्रदर्शन करने को लेकर दर्ज किए गए थे। सरकार का कहना रहा है कि इन मामलों का उद्देश्य राजनीतिक प्रतिशोध था और इन्हें वापस लेना जनहित में है, ताकि जनप्रतिनिधि बिना किसी कानूनी दबाव के

अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

हालांकि, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 65 में से केवल 15 मामलों को वापस लेने की अनुमति दी थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि लंबित सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दर्ज पांच मामले पहले ही निपट चुके हैं, जिससे उनकी स्थिति पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने कई मामलों को गंभीर प्रकृति का मानते हुए वापस लेने से इनकार कर दिया था। इनमें सरकारी कर्मचारी पर हमला, आपराधिक धमकी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज मामले शामिल थे, जिन्हें अदालत ने कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर बताया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने सभी मामलों की प्रकृति को समान दृष्टि से नहीं देखा और कई ऐसे मामलों को भी गंभीर मान लिया, जो वस्तुतः राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े थे। राज्य सरकार का यह भी तर्क है कि अभियोजन वापस लेने का अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत सरकार को प्राप्त है और इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करना नहीं, बल्कि अनावश्यक मुकदमों का बोझ कम करना है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के ही एक अहम निर्णय का हवाला दिया था। अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ (2020) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जन प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए अदालत की अनुमति अनिवार्य होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सत्ता में बैठी सरकारें अपने राजनीतिक हितों के लिए कानून का दुरुपयोग न करें। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सभी मामलों को एक साथ वापस लेने की अनुमति देने से इनकार किया था और केवल उन मामलों को मंजूरी दी थी, जिन्हें उसने कम गंभीर और राजनीतिक प्रकृति का माना।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दिए जाने को सुक्खू सरकार अपनी आंशिक जीत के रूप में देख रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शीर्ष अदालत में वे यह साबित करेंगे कि जिन मामलों को वापस लेने की मांग की गई है, वे लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग से जुड़े हैं और इनका आपराधिकरण राजनीति को बदनाम करने का प्रयास मात्र था। वहीं भाजपा ने इस पूरे मामले को कानून के शासन पर हमला बताते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सत्ता में आते ही अपने नेताओं को कानूनी मामलों से राहत दिलाने की कोशिश कर रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले का फैसला केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशभर में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट सरकार की दलीलों को स्वीकार करता है, तो भविष्य में अन्य राज्य सरकारें भी इसी तरह के मामलों में राहत मांग सकती हैं। दूसरी ओर, यदि अदालत हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है, तो यह संदेश जाएगा कि जनप्रतिनिधियों के मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे वह राजनीतिक आंदोलन से ही क्यों न जुड़े हों। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी करना और सुनवाई की तारीख तय करना इस बात का संकेत है कि अदालत इस संवेदनशील मुद्दे पर विस्तृत विचार करना चाहती है

एपस्टीन फाइलों का विस्फोट, यूरोपीय सत्ता गलियारों में भूचाल

जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी गोपनीय फाइलों के सार्वजनिक होते ही यूरोप और अमेरिका की राजनीति में ऐसा तूफान उठा है, जिसने कई दशकों से स्थापित सत्ता समीकरणों को हिला कर रख दिया है। जिन नामों को अब तक प्रभाव, प्रतिष्ठा और ताकत का पर्याय माना जाता था, वे अचानक नैतिक सवालों के कठघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। यह मामला केवल किसी एक देश या व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी आंच ब्रिटेन से लेकर नॉर्वे, स्वीडन और अमेरिका तक फैल चुकी है। एपस्टीन के अपराधी सिद्ध हो जाने के बावजूद उससे संपर्क बनाए रखने, निजी आयोजनों में शामिल होने या कथित दोस्ती निभाने के आरोपों ने कई राजनयिकों और नेताओं के करियर पर विराम लगा दिया है।

ब्रिटेन में इस खुलासे का असर सबसे ज्यादा तीखा दिखाई दे रहा है। यहां पूर्व शीर्ष राजनयिक पीटर मेंडलसन को उनके पद से हटाया जा चुका है और उनके खिलाफ कानूनी जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। विपक्ष और मीडिया का आरोप है कि मेंडलसन ने एपस्टीन के आपराधिक अतीत के सार्वजनिक हो जाने के बाद भी उससे संपर्क बनाए रखा, जिससे ब्रिटेन की कूटनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा। इस विवाद की लपटें मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर तक भी पहुंच गई हैं। उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अहम राजनयिक जिम्मेदारी सौंपी, जिसके एपस्टीन से संबंध पहले से ज्ञात थे। इससे सरकार की नैतिक प्रतिबद्धता और निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

शाही परिवार के लिए यह मामला और भी

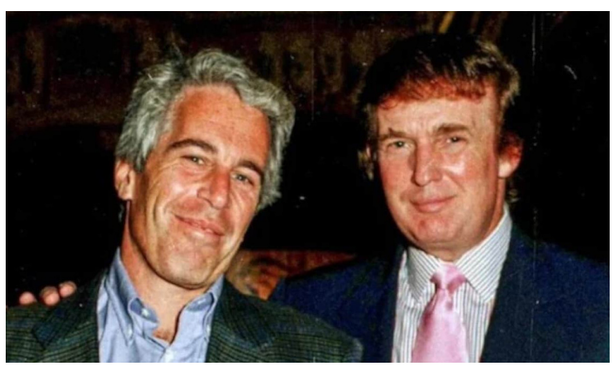

अधिक शर्मिंदगी भरा साबित हुआ है। प्रिंस एंड्रयू पहले ही इस विवाद के चलते अपने शाही खिताब, सरकारी आवास और सार्वजनिक दायित्वों से वंचित किए जा चुके हैं। एपस्टीन से उनकी नजदीकियों और एक पीड़िता के साथ हुए महंगे समझौते ने शाही प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया। ब्रिटिश राजशाही, जो आमतौर पर विवादों से दूरी बनाए रखने के लिए जानी जाती है, इस मामले में कठोर कदम उठाने को मजबूर हुई। इसका संदेश यूरोप के अन्य राजघरानों तक भी गया, जहां अब पुराने संबंधों और निजी मेल-जोल की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है।

यूरोप के अन्य देशों में भी इस खुलासे ने राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी है। नॉर्वे में पूर्व प्रधानमंत्री थोर्बयॉर्न यागलैंड के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें एपस्टीन से जुड़े वित्तीय लेन-देन और संपर्कों की पड़ताल की जा रही है। वहीं नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे-मैरिट को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी है, क्योंकि उनके और एपस्टीन के बीच पुरानी दोस्ती के प्रमाण सामने आए हैं। इस प्रकरण ने तब और गंभीर रूप ले लिया, जब एक राजनयिक दंपती के बच्चों को एपस्टीन की वसीयत से बड़ी धनराशि मिलने की जानकारी सार्वजनिक हुई। इस खुलासे ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एपस्टीन अपने प्रभाव और धन का इस्तेमाल सत्ता के गलियारों में जगह बनाने के लिए करता था।

स्वीडन और स्लोवाकिया जैसे देशों में भी वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे सामने आए हैं। हालांकि कई मामलों में सीधे तौर पर यौन शोषण के आरोप नहीं हैं, लेकिन एपस्टीन जैसे अपराधी से नजदीकी संबंध बनाए रखने को ही नैतिक अपराध मानते हुए कार्रवाई की गई है। यूरोप में यह बहस तेज हो गई है कि सार्वजनिक जीवन में बैठे लोगों के निजी संबंध भी उनकी जवाबदेही के दायरे में आने चाहिए या नहीं। इस बहस ने राजनीति में पारदर्शिता और नैतिकता के नए मानक तय करने की मांग को और मजबूती दी है।

अमेरिका में भी इस मामले ने कई बड़े नामों को घेरा है, हालांकि वहां कार्रवाई की रफ्तार यूरोप की तुलना में धीमी रही है। पूर्व वित्त मंत्री लैरी समर्स और कुछ प्रभावशाली लॉ फर्मों के प्रमुखों को अपने पद छोड़ने पड़े हैं। एपस्टीन के साथ उनकी पेशेवर या सामाजिक नजदीकियों को लेकर तीखी आलोचना हुई है। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के नाम भी बार-बार चर्चा में आए हैं, लेकिन किसी पीड़िता द्वारा सीधे आरोप न लगाए जाने के कारण वे अब तक कानूनी शिकंजे से बाहर हैं। इसके बावजूद सार्वजनिक दबाव लगातार बढ़ रहा है और अमेरिकी समाज में भी यह सवाल उठने लगा है कि क्या ताकतवर लोग कानून से ऊपर हैं।

एपस्टीन फाइलों का यह खुलासा अब केवल अतीत के अपराधों की जांच तक सीमित नहीं रहा। यह सत्ता, प्रभाव और जवाबदेही के रिश्ते को उजागर करने वाला मामला बन चुका है। यूरोप में जहां एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, वहीं यह संदेश भी साफ है कि केवल कानूनी दोष नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी सार्वजनिक जीवन का अहम हिस्सा है। आने वाले दिनों में इस मामले से और नाम सामने आने की आशंका जताई जा रही है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि एपस्टीन फाइलों का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तूफान कई और करियर, कई और प्रतिष्ठाओं को अपने साथ बहा ले जा सकता है।

गढ़चिरौली के जंगलों में निर्णायक वार, सात नक्सलियों का अंत

गढ़चिरौली जिले के घने और दुर्गम जंगलों में सुरक्षाबलों ने एक बड़े और निर्णायक नक्सल विरोधी अभियान को अंजाम देते हुए सात इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। यह मुठभेड़ कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि तीन दिन और तीन रात तक चली लगातार घेराबंदी, रणनीतिक मूवमेंट और धैर्यपूर्ण ऑपरेशन का नतीजा रही। शनिवार को पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने प्रेस वार्ता कर इस अभियान की आधिकारिक पुष्टि की और बताया कि मारे गए नक्सलियों पर कुल 71 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इस कार्रवाई को हाल के वर्षों में क्षेत्र में नक्सल नेटवर्क को मिली सबसे बड़ी चोट के रूप में देखा जा रहा है।

सुरक्षाबलों को नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। जंगलों में छिपे नक्सली कैडर लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे और इलाके की भौगोलिक कठिनाइयों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद सुरक्षाबलों ने क्षेत्र को चारों ओर से घेरते हुए दबाव बनाए रखा। रात-दिन चलने वाली इस मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों की ओर से भारी फायरिंग की गई, जिसका जवानों ने संयम और साहस के साथ जवाब दिया। गोलियों की आवाज़ों और विस्फोटों के बीच पूरा इलाका कई घंटों तक युद्ध क्षेत्र में तब्दील रहा।

इस अभियान में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता तो मिली, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। मुठभेड़ के दौरान जवान दीपक मडावी वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान ने पूरे अभियान को और अधिक भावनात्मक और संवेदनशील बना दिया। एक अन्य जवान भी इस कार्रवाई में घायल हुआ, हालांकि अधिकारियों ने बताया कि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है और उसे बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने शहीद जवान के साहस और कर्तव्यनिष्ठा को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी।

मारे गए नक्सलियों में संगठन के शीर्ष और अनुभवी कैडर शामिल हैं, जिससे इस कार्रवाई का महत्व और बढ़ जाता है। पुलिस के मुताबिक इनमें दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े प्रभाकर उर्फ रवि, जिस पर 25 लाख रुपये का इनाम था, और पगु मोड्यम, जिस पर 16 लाख रुपये का इनाम घोषित था, जैसे कमांडर स्तर के नक्सली शामिल हैं। इनके अलावा अन्य मारे गए नक्सलियों पर भी 4 से 8 लाख रुपये तक के इनाम घोषित थे। ये सभी लंबे समय से सक्रिय थे और कई गंभीर वारदातों में शामिल रहे थे।

अधिकारियों के अनुसार इन नक्सलियों के खिलाफ हत्या, सुरक्षाबलों पर हमले, विस्फोट, पुलिस मुठभेड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे अनेक संगीन मामले दर्ज थे। ये नक्सली न केवल स्थानीय स्तर पर हिंसा फैलाने में सक्रिय थे, बल्कि नए कैडर की भर्ती, हथियारों की आपूर्ति और रणनीति बनाने में भी अहम भूमिका निभा रहे थे। ऐसे में इनका मारा जाना नक्सल संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिससे उनके नेटवर्क और मनोबल पर सीधा असर पड़ेगा।

मुठभेड़ के बाद भी इलाके में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में सघन सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ नक्सली घायल अवस्था में जंगलों के भीतर भागने में सफल हो गए हों।

एकतानगर स्टेशन से हरित भविष्य की ओर बढ़ती भारतीय रेल

वडोदरा। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने सात फरवरी 2026 को गुजरात के पहले ग्रीन रेलवे स्टेशन एकतानगर का दौरा कर न केवल स्टेशन की आधुनिक सुविधाओं और हरित तकनीक आधारित विकास कार्यों का जायजा लिया, बल्कि वडोदरा मंडल में चल रही परियोजनाओं, भविष्य की योजनाओं और संरक्षा से जुड़े प्रयासों की भी विस्तृत समीक्षा की। यह दौरा भारतीय रेल के उस विज़न को मजबूती देता नजर आया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, यात्री सुविधा और परिचालन दक्षता को एक साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

एकतानगर रेलवे स्टेशन आज देश के सबसे सुंदर और आधुनिक रेलवे स्टेशनों में शुमार किया जाता है। गुजरात के पहले "ग्रीन रेलवे स्टेशन" के रूप में विकसित इस स्टेशन में सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता जैसे पर्यावरण अनुकूल उपायों को प्राथमिकता दी गई है। महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने स्टेशन परिसर का गहन निरीक्षण करते हुए स्वच्छता व्यवस्था, यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, हरित तकनीक के उपयोग और रखरखाव के स्तर की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत के दौरान इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि किस तरह एकतानगर स्टेशन को पर्यावरण संरक्षण और आधुनिकता का उदाहरण बनाया गया है।

इस अवसर पर वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने महाप्रबंधक को मंडल में चल रही विभिन्न परियोजनाओं और हाल के वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि एकतानगर स्टेशन पर ट्रेन परिचालन क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए एक अतिरिक्त लूप लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इससे भविष्य में ट्रेनों के ठहराव और परिचालन में अधिक लचीलापन आएगा और यात्रियों को बेहतर सेवा मिल सकेगी। साथ ही डभोई और एकतानगर रेल खंड में कैटल रन ओवर की घटनाओं को रोकने के लिए मेटल क्रैश बैरियर लगाने का कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस पहल से न केवल संरक्षा में सुधार होगा, बल्कि ट्रेनों की पंक्चुअलिटी भी बेहतर होगी, जो यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

भारतीय रेल के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास की दिशा में अमृत भारत स्टेशन योजना एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उभरी है। इसी योजना के तहत गोधरा स्टेशन का कायाकल्प कार्य पूरा हो चुका है। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न को साकार करते हुए गोधरा स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है और जल्द ही प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा प्रतापनगर और डभोई स्टेशनों पर भी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास कार्य तेजी से जारी हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन दोनों स्टेशनों पर 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का निर्माण अंतिम चरण में है, जिससे प्लेटफार्मों के बीच आवागमन सुरक्षित और सुगम हो सकेगा।

वडोदरा मंडल के इस रेल खंड में परिचालन क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी कई अहम कदम उठाए गए हैं। कुंदेला और तिलकवाड़ा स्टेशनों को 'बी' श्रेणी के स्टेशनों में परिवर्तित किया गया है, जिससे न केवल स्टेशन सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि पूरे सेक्शन की क्षमता में भी वृद्धि संभव होगी। इससे भविष्य में यात्री और मालगाड़ियों के संचालन को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा।

संपादकीय

कम हिमपात से संकट में हिमालयी जीवनरेखा

हिमाचल प्रदेश, जिसे कभी बर्फ की चादर में लिपटा पहाड़ी स्वर्ग कहा जाता था, आज जलवायु परिवर्तन की मार से जूझ रहा है। बीते लगभग छह वर्षों में राज्य में बर्फबारी के दिनों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। ठंडे प्री-मानसून महीनों का सिमटना, सर्दियों का अपेक्षाकृत गर्म होना और देर से या न के बराबर बर्फबारी- ये सभी संकेत हिमालयी जलवायु के बदलते स्वरूप की ओर इशारा कर रहे हैं। बदलती जलवायु, बदलता हिमाचल : पहले नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में ही शिमला, मनाली और आसपास के इलाके बर्फ से ढक जाते थे। आज स्थिति यह है कि कई बार जनवरी का महीना भी बिना बर्फ के निकल जाता है। जैसा इस बार हुआ है, व्हाइट क्रिसमस और नए साल के जश्न में बर्फबारी को तरसे पर्यटकों को 26 जनवरी के बाद का इंतजार करना पड़ा। मौसम विभाग और राज्य एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि बर्फबारी की आवृत्ति ही नहीं, उसकी अवधि में भी उल्लेखनीय कमी आई है। 70 के दशक में अकेले शिमला में बर्फबारी के जो दिन 20 से 30 हुआ करते थे, अब घट कर मात्र 3 से 5 ही रह गए हैं। मात्र यही नहीं, हिम कॉस्ट और प्रदेश जलवायु परिवर्तन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार चार प्रमुख जल धाराओं चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के प्रवाह क्षेत्र में कुल हिमाच्छादित क्षेत्रफल 2018 के 20218 वर्ग किमी के मुकाबले 14 फीसदी घट कर 17437 वर्ग किमी रह गया जो कि न सिर्फ जलवायु परिवर्तन का द्योतक है, अपितु गंभीर पारिस्थितिकीय संकट की ओर इशारा कर रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभों का कमजोर पडना और उनके आगमन का समय बदलना इसका एक प्रमुख कारण है। तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के कारण बर्फ अब लंबे समय तक टिक नहीं पाती, फलतः ग्लेशियर भी तेजी से सिकुड़ रहे हैं। पर्यटन उद्योग पर सीधा असर : हिमाचल का शीतकालीन पर्यटन मुख्यतः बर्फ पर आधारित है। शिमला, कुफरी, नारकंडा और मनाली-रोहतांग जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फ देखने आने वाले सैलानी अब निराश हो रहे हैं। इसका असर होटल व्यवसाय, टैक्सी सेवाओं, स्की प्रशिक्षकों और स्थानीय दुकानदारों पर साफ दिखता है। कुछ जगहों पर कृत्रिम बर्फ बनाने के प्रयास भी किए गए, लेकिन वे प्राकृतिक बर्फ का विकल्प साबित नहीं हो सके। इससे पर्यटन अर्थव्यवस्था अस्थिर होती जा रही है। सेब की खेती पर मंडराता संकटः हिमाचल की पहचान रही सेब की खेती भी गहरे संकट में है। सेब के पेड़ों को अच्छी पैदावार के लिए पर्याप्त चिलिंग ऑवर्स (न्यून तापमान की अवधि) की आवश्यकता होती है, जो कि 1200 से 1900 घंटे, जबकि सामान्य तापमान 7 डिग्री से कम हो, वो अब पूरी नहीं हो पा रही। इसी के चलते कुल्लू व शिमला के कई किसानों ने अनुभव किया कि सामान्यतः 5000 फीट पर स्थिर रही एप्पल बेल्ट अब 6000 फीट पर पहुंच गई है। उनका कहना है कि फूल समय से पहले आ जाते हैं, लेकिन तापमान में अचानक वृद्धि या असमय बारिश के कारण फल गिर जाते हैं। परिणामस्वरूप, कई क्षेत्रों में किसान सेब छोडक़र सब्जियों या अन्य नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल के निचले इलाकों की बदलती कृषि कथा : हिमाचल प्रदेश की पहचान केवल सेब तक सीमित नहीं है। आड़ू, खुबानी, आलूबुखारा, चेरी और नेक्टेरिन जैसे स्टोन फ्रूट्स लंबे समय से राज्य के निचले और मध्य पर्वतीय इलाकों की कृषि अर्थव्यवस्था का अहम आधार रहे हैं। सोलन, सिरमौर, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे जिलों में ये फल न केवल किसानों की आय का प्रमुख स्रोत रहे हैं, बल्कि राज्य को प्रारंभिक सीजन में बाजार तक पहुंच दिलाने वाली फसल भी रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में कम होती सर्दी और लगभग गायब होती बर्फ ने इस पारंपरिक फलोत्पादन व्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया है। स्टोन फ्रूट्स और सर्दी का रिश्ता : सेब की तरह ही स्टोन फ्रूट्स की खेती का आधार भी है चिलिंग ऑवर्स, यानी सर्दियों के दौरान एक निश्चित अवधि तक कम तापमान। यही ठंड पौधों को सुप्तावस्था से बाहर निकालकर समय पर फूल और बाद में फल देने की उनकी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। हिमाचल के निचले इलाकों में पहले दिसंबर-जनवरी की ठंड इस आवश्यकता को पूरा कर देती थी, भले ही वहां भारी बर्फ न गिरती हो। किंतु अब स्थिति तेजी से बदल रही है। घटती सर्दी, बिगड़ता जैविक चक्र पिछले एक दशक में निचले हिमाचली क्षेत्रों में सर्दियों का औसत तापमान लगातार बढ़ा है।

ईरान को सबक सिखाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं ट्रंप

> यह कदम ऐसे समय आया है जब ओमान में दोनों देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है। कई सप्ताह की बयानबाजी और धमकियों के बाद शुरू हुई यह बातचीत तनाव कम करने की कोशिश मानी जा रही है, पर जमीन पर हालात अब भी तने हुए हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी चरम पर होने के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी कर उन सभी देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की चेतावनी दी है जो ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार जारी रखेंगे। आदेश में शुल्क की दर तय नहीं की गई है, पर उदाहरण के तौर पर पच्चीस प्रतिशत का जिक्र है। साफ कहा गया है कि जो भी देश सीधे या परोक्ष रूप से ईरान से सामान या सेवा खरीदेगा, उस पर यह शुल्क लगाया जा सकता है। ट्रंप ने अलग से बयान देते हुए दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए।यह कदम ऐसे समय आया है जब ओमान में दोनों देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है। कई सप्ताह की बयानबाजी और धमकियों के बाद शुरू हुई यह बातचीत तनाव कम करने की कोशिश मानी जा रही है, पर जमीन पर हालात अब भी तने हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ओमान में वार्ता को अच्छी शुरुआत बताया, लेकिन साथ ही कहा कि अविश्वास का माहौल गहरा है, खासकर इसलिए कि हाल ही में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ट्रंप ने भी वार्ता को बहुत अच्छी बताया, पर साथ में चेतावनी जोड़ी कि यदि समझौता नहीं हुआ तो नतीजे बहुत सख्त होंगे।

अमेरिका का कहना है कि वह केवल परमाणु कार्यक्रम नहीं, बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, सशस्त्र समूहों को समर्थन और अपने नागरिकों के साथ व्यवहार जैसे मुद्दे भी बातचीत में शामिल करना चाहता है। दूसरी ओर तेहरान का रुख साफ है कि चर्चा केवल परमाणु कार्यक्रम पर होगी और उसे यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिलना चाहिए। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वह हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा।

हम आपको बता दें कि इस तनातनी की जड़ें पिछले एक दशक में लिए गए फैसलों में हैं। वर्ष 2015 के परमाणु समझौते के तहत ईरान को सीमित स्तर तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति थी और उस पर सख्त निगरानी थी। बदले में उस पर लगे कई प्रतिबंध हटाए गए थे। लेकिन ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में वर्ष 2018 में इस समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था और कठोर प्रतिबंध फिर लगा दिए थे। तेल निर्यात, जहाजरानी और बैंक तंत्र पर पाबंदियों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी चोट दी। जवाब में ईरान ने समझौते की कई शर्तों से आगे बढ़ कर संवर्धन करना शुरू कर दिया।

बीते वर्षों में हालात और बिगड़े। वर्ष 2020 में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी अमेरिकी हमले में मारे गए, जिससे टकराव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। फिर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध फिर लगाने की कोशिशें हुईं। वर्ष 2025 में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने कतर में एक अमेरिकी ठिकाने पर मिसाइल दागी, हालांकि जान का नुकसान नहीं हुआ। पिछले वर्ष पश्चिमी देशों के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध फिर लागू हुए। अब ताजा कदम के तहत अमेरिका ने ईरानी तेल और पेट्रो रसायन से जुड़े पंद्रह संस्थानों और कई जहाजों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर ईरान को चेताया कि किसी भी हमले का जोरदार जवाब मिलेगा। उनका कहना है कि अमेरिका के साथ तालमेल बहुत गहरा है, इसलिए अंतिम फैसला ट्रंप ही करेंगे। ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान बातचीत इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अमेरिकी हमले से बचना चाहता है और अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा इलाके में आगे बढ़ रहा है।

सवाल यह है कि क्या यह पूरी कवायद शांति की राह है या दबाव की राजनीति का नया दौर? ट्रंप का शुल्क हथियार दरअसल आर्थिक घेराबंदी का विस्तार है। संदेश साफ है कि जो ईरान से नाता रखेगा, वह अमेरिकी बाजार से हाथ धो सकता है। यह नीति कई देशों को कठिन दुविधा में डालेगी, खासकर वे देश जो ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरानी तेल पर निर्भर हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री रास्तों की सुरक्षा और पश्चिम एशिया की सामरिक स्थिरता पर सीधा असर पड़ेगा।

सामरिक दृष्टि से यह रस्साकशी खतरनाक है। एक ओर बातचीत चल रही है, दूसरी ओर युद्ध की तैयारी जैसे संकेत दिए जा रहे हैं। बेड़े की तैनाती, मिसाइल की चर्चा और प्रतिबंधों की बौछार मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जहां एक छोटी चिंगारी भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। ईरान भी झुकने के मूड़ में नहीं दिखता और वह बार बार अपने अधिकार की बात दोहरा रहा है। बहरहाल, हकीकत यह है कि न तो केवल दबाव से समाधान निकलेगा, न केवल बयान से। यदि दोनों पक्ष सच में टकराव टालना चाहते हैं तो उन्हें भरोसे की बहाली, चरणबद्ध रियायत और स्पष्ट लक्ष्यों की राह पकड़नी होगी। वरना शुल्क, प्रतिबंध और हमले का यह चक्र पूरे इलाके को अस्थिर कर देगा और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर दूर तक जाएगा। अभी भी समय है कि शक्ति प्रदर्शन की जगह समझदारी दिखाई जाए, नहीं तो आने वाले दिन और ज्यादा उथल पुथल लेकर आ सकते हैं।

प्रेरणा

वैराग्य: जब सुख भी बोझ लगने लगे

वैराग्य का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को उसी रूप में देख पाना है जैसा वह वास्तव में है। यह वह क्षण है जब मन पूछता है—क्या मैं सचमुच सुखी हूं, या केवल उत्तेजित हूं? क्या यह जो खुशी मुझे मिली है, वह मुझे शांत कर रही है या भीतर कहीं और अधिक बेचैनी भर रही है? कोई भी खुशी, चाहे वह कितनी ही मनचाही क्यों न हो, क्या उसे बांधकर रखा जा सकता है? बहुत अधिक हंसी, बहुत अधिक उत्साह, बहुत अधिक आनंद—कुछ समय बाद असहनीय हो जाता है। तब मन चाहता है कि सब कुछ छोड़कर कुछ देर चुपचाप बैठा जाए, बिना किसी इच्छा, बिना किसी लक्ष्य के। जिस दिन यह अनुभूति स्पष्ट होने लगे, उसी दिन वैराग्य का पहला बीज भीतर गिरता है।

हम अक्सर मानते हैं कि दुख ही कष्ट देता है, पर वास्तविक समझ तब आती है जब यह दिखने लगे कि सुख भी कष्ट ही है। सुख की प्रकृति है कि वह उत्तेजना लाता है, अपेक्षा लाता है, पुनरावृत्ति की मांग करता है। जो आज सुख देता है, वही कल बोझ बन जाता है। जब यह बोध जागता है कि सुख स्वयं में अशांति है, तभी ज्ञानोदय की शुरुआत होती है। उसी दिन मन पहली बार शांति की ओर झुकता है। अब उसे और अधिक पाने की भूख नहीं, बल्कि स्थिर होने की आकांक्षा होती है। यही वैराग्य का प्रवेश द्वार है।

आज का मन अत्यंत असंवेदनशील हो चुका है। छोटी प्रसन्नता से वह संतुष्ट नहीं होता। उसे लगातार और चाहिए—और खुशी, और सफलता, और मान्यता। दूसरों से आगे निकलने की व्यग्रता, उनसे बेहतर दिखने की बेचैनी, उनसे अधिक पाने की लालसा—यही आधुनिक जीवन का स्वभाव बन गया है। हम एक व्यग्रता से दूसरी व्यग्रता की ओर भागते रहते हैं। निराशा भी व्यग्रता है और अत्यधिक प्रसन्नता भी। दोनों ही स्थितियां मन को अस्थिर रखती हैं। जीवन जैसे एक झूले पर लटका है, जो कभी सुख की ओर जाता है तो कभी दुख की ओर, पर कहीं टिकता नहीं। वैराग्य इस झूले से उतरने का नाम है।

वैराग्य सुख और दुख के पार की अवस्था है। वहां बड़ी से बड़ी खुशी भी मन को उछाल नहीं सकती और बड़ा से बड़ा दुख भी मन को तोड़ नहीं सकता। यही स्थितप्रज्ञता है, यही बुद्धत्व है। यदि स्वर्ग का सिंहासन भी सामने रख दिया जाए, तो भी वैरागी की आंखों में कोई चमक नहीं आती, क्योंकि वह जानता है कि सिंहासन भी एक अवस्था है, स्थायी सत्य नहीं। उसकी उपलब्धि बाहर नहीं, भीतर है। वह किसी पद, धन या प्रशंसा पर निर्भर नहीं करता। उसकी स्थिरता ही उसकी समृद्धि है। वैराग्य कोई विधि नहीं है जिसे सीखा जा सके। ध्यान की तकनीकें सिखाई जा सकती हैं, पूजा-पाठ के नियम बताए जा सकते हैं, पर वैराग्य सिखाया नहीं जा सकता। वह जीवन के अनुभवों से स्वयं प्रकट होता है। बार-बार सुख पाकर भी तृप्त न होना, बार-बार गिरकर भी उठना, और अंततः एक दिन यह समझ लेना कि यह दौड़ निरर्थक है—यहीं से वैराग्य जन्म लेता है। कभी-कभी यह किसी गुरु के सान्निध्य में सहज ही खिल उठता है। पुस्तकों में इसके शब्द मिल सकते हैं, पर वैराग्य स्वयं केवल अनुभव से आता है।

वैराग्य संसार की सर्वोच्च प्रज्ञा है, क्योंकि उसे किसी भी प्रलोभन से हिलाया नहीं जा सकता। संसार में लगभग हर चीज का सौदा संभव है। पद बिकते हैं, सिद्धांत बिकते हैं, विचार बिकते हैं। साधारण व्यक्ति थोड़े से लालच में अपने मूल्य त्याग सकता है। बीस-तीस लाख के लिए वह वह सब करने को तैयार हो सकता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर वैरागी नहीं। यदि उससे कहा जाए कि झूठ बोल दो और बदले में एक करोड़ रुपए मिलेंगे, तो सामान्य मन तुरंत तर्क गढ़ने लगेगा—इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, इस पैसे से तो मैं बहुत भलाई कर सकता हूं। मन अपने स्वार्थ को नैतिकता के आवरण में छिपा लेता है। पर वैराग्य तर्क नहीं करता। वह साफ देखता है कि झूठ, झूठ ही है।

संत कबीर से जुड़ी एक घटना इस सत्य को उजागर करती है। एक पंडित ने एक वेश्या से कहा कि वह कबीर के सत्संग में जाकर उनके साथ संबंध का संकेत दे, ताकि लोगों के मन में संदेह पैदा हो। वह स्त्री आत्मसम्मानी थी, उसने मना किया। पर जब उसे सोने की मोहरों का लालच दिया गया, तो वह राजी हो गई। सत्संग में उसने वही कहा जो सिखाया गया था। कबीर का उत्तर अद्भुत था—मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हूं, तुम अब तक कहां थी? आओ, बैठो, मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। इस वाक्य ने उपस्थित जनसमूह को हिला दिया।

कई लोग, जो अब तक कबीर के शब्दों से प्रभावित थे, उस एक घटना के बाद उनसे दूर हो गए। क्योंकि उनका संबंध कबीर से भीतर का नहीं, केवल विचारों का था। एक घटना ने उनका विश्वास डिगा दिया। कबीर शांत रहे। उन्होंने न सफाई दी, न प्रतिरोध किया। बाद में वही स्त्री सत्य से अधिक देर दूर न रह सकी और राजा के पास जाकर पूरी बात स्वीकार कर ली। उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। यह वैराग्य की शक्ति है। जहां वैराग्य होता है, वहां सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। यदि किसी भी स्थिति का सत्य जानना हो, तो पहले भीतर शांत और वैरागी होना आवश्यक है। अशांत मन कभी सत्य नहीं देख सकता। शांति कमजोरी नहीं है, वह सबसे बड़ी शक्ति है। वास्तविक आत्मीयता, वास्तविक करुणा और वास्तविक विवेक वैराग्य में ही संभव है। वैराग्य जीवन से मुंह मोड़ना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को बिना आसक्ति और बिना भय के जीना सिखाता है। वही व्यक्ति सच में समृद्ध है, जिसे कुछ भी लुभा नहीं सकता और कुछ भी विचलित नहीं कर सकता। यही वैराग्य की परम उपलब्धि है।

मर्यादा हनन का सदन

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय संबोधन में खुलासा किया है कि भारत 9 देशों के साथ व्यापार समझौते कर चुका है और 24 देशों के साथ वार्ताएं जारी हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी संसद को बताया है कि भारत और खाड़ी देश सहयोग परिषद् के 6 देशों के बीच गुरुवार को 'मुक्त व्यापार समझौते' पर बातचीत शुरू करने की शर्तों पर सहमति बन गई है। इन देशों में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल हैं। वाणिज्य मंत्री ने यह भी खुलासा किया है कि भारत-अमरीका का साझा बयान 4-5 दिन में सार्वजनिक हो जाएगा, जबकि मार्च मध्य में समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। जाहिर है कि अभी बहुत कुछ तय होना है। सिर्फ दोनों देश सैद्धांतिक तौर पर सहमत हुए हैं। इस संदर्भ में विपक्ष का प्रलाप समझ के परे है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने यहां तक कह दिया कि समझौते से भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे। किसी ने कहा कि रात के अंधेरे में किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है। आखिर विपक्ष के नेता 'किसान-विरोधी समझौते' पर विलाप क्यों कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्पष्ट कर चुके हैं कि कृषि और डेयरी क्षेत्रों को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया है? किसान और पशुपालक पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित हैं। यथार्थ यह भी है कि कृषि के कई उत्पादों का भारत को आयात करना पड़ता है, क्योंकि हमारे किसान उतना उत्पादन नहीं कर सकते, जितनी खपत है। लोगों को तो चाहिए। हम दालें, सूखे मेवे, खाद्य तेल, फल और सब्जियों का 26 अरब डॉलर का आयात करते हैं। यानी विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में मौजूद हैं और अरबों डॉलर का व्यापार कर रही हैं। बेशक अमरीका से इन कृषि उत्पादों का आयात कम किया जाता है। यदि अमरीका से यह आयात सस्ता पड़ेगा, तो क्या हम समझौते से चिपके रहेंगे और अमरीका से ये उत्पाद नहीं खरीदेंगे? बेहद संवेदनशील सवाल है। चूंकि देश में इन उत्पादों की खपत है, जरूरत है, लिहाजा आयात करना 'राष्ट्रीय मजबूरी' है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रपट सामने आई है कि यदि अमरीका से डेयरी उत्पाद भारत में आए, तो यहां के दुग्ध उत्पादक किसानों को करीब 1,03,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। क्या यह सटीक और व्यावहारिक रपट है? यह भी दलील दी जा रही है कि अमरीका में गायों को मांस और चर्बी आदि खिलाते हैं, लिहाजा उनके दूध में उसके प्रभाव भी शामिल होंगे और इस तरह असंख्य भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। कुल मिला कर ऐसा प्रतीत होता है मानो कृषि और डेयरी क्षेत्र आज भी अपंग-अधूरे हैं। हालांकि भारत में दुग्ध कारोबार 7.5-9 लाख करोड़ रुपए का है। हम विश्व में सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश होने का भी दावा करते रहे हैं। हमने दूध की कमी और संकट के दौर भी देखे और झेले हैं। भारत में 13 जनवरी, 1970 को जब 'ऑपरेशन फ्लड' का आगाज किया गया था, तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम करार दिया गया था। उसे 'श्वेत क्रांति' का नाम भी दिया गया था, लेकिन उससे पहले भारत दूध की कमी वाला देश था। इस 'श्वेत क्रांति' के सूत्रधार थे-डॉ. वर्गीज कुरियन। लगभग ऐसा ही हाल कृषि का है। आजादी के 78 सालों के बाद भी सहस्र वर्षों पुरानी कृषि इस स्थिति में नहीं है कि विदेशी प्रतिस्पद्र्धा का मुकाबला कर सके। किसान भी गरीब है और सरकारी मदद के भरोसे रहता है, लिहाजा भारत को आज भी कृषि और किसान को संरक्षण देना पड़ रहा है। व्यापार समझौतों पर बातचीत के दौरान भारत को इन दो मुद्दों पर अड़े रहना पड़ता है। अलबत्ता यूरोपीय संघ और अमरीका के साथ व्यापार समझौते कभी के तय हो गए होते! किसान भारत की राजनीतिक बाध्यता भी हैं। इस वोट बैंक के दबाव के आगे सभी को झुकना पड़ता है। अमरीका की जीडीपी में कृषि का योगदान मात्र 1 फीसदी है और यूरोपीय संघ में 1.6 फीसदी है, लेकिन भारतीय जीडीपी में कृषि का योगदान आज भी 16.3 फीसदी है, लिहाजा यह बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। भारत सरकार को इन पहलुओं पर विचार करते हुए कृषि को स्वायत्त और 'बड़ा बच्चा' बनने देना चाहिए। किसानों की केंद्र सरकार से कई अपेक्षाएं हैं, जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए।

अभियान

देवगुरु बृहस्पति की तपोभूमि देवगुरु पर्वत उत्तराखंड

देवभूमि उत्तराखंड की पहचान केवल उसके हिमालयी सौंदर्य से नहीं, बल्कि उन असंख्य आध्यात्मिक स्थलों से है जहां आज भी तप, साधना और चेतना की अविरल धारा प्रवाहित होती प्रतीत होती है। इन्हीं दिव्य स्थलों में एक अत्यंत रहस्यमय और कम चर्चित स्थान है देवगुरु पर्वत, जहां देवताओं के गुरु बृहस्पति देव का प्राचीन मंदिर स्थित है। समुद्र तल से लगभग आठ हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत शिखर न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक सशक्त केंद्र भी माना जाता है। यहां पहुंचने वाला व्यक्ति अनायास ही अनुभव करता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर उतर रही हो और मन की चंचलता धीरे-धीरे शांत हो रही हो।

नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक में स्थित यह पर्वत क्षेत्र आज भी आधुनिक कोलाहल से लगभग अछूता है। घने जंगल, ऊंचे वृक्ष, स्वच्छ हवा और दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं इस स्थान को स्वाभाविक रूप से साधना योग्य बना देती हैं। यहां की पगडंडियों पर चलते हुए ऐसा लगता है मानो समय की गति धीमी हो गई हो। मोबाइल सिग्नल भले कमजोर हो जाए, पर आत्मा का संकेत यहां स्पष्ट होने लगता है। यही कारण है कि यह स्थल केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आत्मिक विश्राम की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब-जब देवताओं के समक्ष कोई गंभीर संकट उत्पन्न होता था, तब वे अपने गुरु बृहस्पति के मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर देखते थे। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति ने इसी पर्वत पर बैठकर दीर्घकाल तक तपस्या और चिंतन किया। यहीं उन्होंने देवताओं को धर्म, नीति और विवेक का मार्ग दिखाया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें देवताओं का गुरु पद प्रदान किया और नवग्रह मंडल में स्थान दिया। इस प्रकार यह पर्वत केवल एक भौतिक स्थल नहीं, बल्कि ब्रह्मज्ञान और निर्णय शक्ति की उत्पत्ति भूमि के रूप में भी प्रतिष्ठित हुआ।

स्थानीय जनमान्यताओं में इस पर्वत का विशेष स्थान है। यहां के ग्रामीण मानते हैं कि यह क्षेत्र ऋषियों और मुनियों की साधना स्थली रहा है। आज भी कई वृद्ध लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में यहां दूर-दूर से साधक ध्यान और तपस्या के लिए आया करते थे। उनका विश्वास है कि इस भूमि की ऊर्जा मनुष्य के भीतर छिपे विवेक को जागृत कर देती है। शायद यही कारण है कि यहां कुछ समय बिताने के बाद व्यक्ति अपने जीवन के प्रश्नों को अधिक स्पष्टता से देखने लगता है।

बृहस्पति देव को ज्ञान, बुद्धि, धर्म, नैतिकता और विस्तार का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को अत्यंत शुभ माना गया है। व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति उसके जीवन की दिशा, शिक्षा, विवाह, धन और आध्यात्मिक उन्नति को प्रभावित करती है। इस मंदिर में आने वाले अधिकांश श्रद्धालु गुरु दोष निवारण, ज्ञान प्राप्ति और जीवन में स्थिरता की कामना लेकर आते हैं। कई लोग मानते हैं कि यहां की गई प्रार्थना केवल बाहरी समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि भीतर एक नई समझ भी जाग्रत करती है।

यह मंदिर विशेष रूप से छात्रों और शिक्षाविदों के बीच आस्था का केंद्र है। परीक्षा से पूर्व, उच्च शिक्षा के आरंभ में या किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले यहां दर्शन करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। श्रद्धालुओं का मानना है कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। अनेक लोग अपने जीवन अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि यहां आने के बाद उनके भीतर आत्मविश्वास और स्पष्टता का भाव बढ़ा है।

हर बृहस्पतिवार को इस मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व होता है। उस दिन मंदिर परिसर में विशेष चहल-पहल रहती है। श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण कर, पीले फूल, चने की दाल, गुड़ और अन्य पीले पदार्थ अर्पित करते हैं। मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा पर्वत उस दिन किसी अदृश्य चेतना से स्पंदित हो उठा हो।

देवगुरु पर्वत की यात्रा स्वयं में एक साधना समान है। हल्द्वानी या काठगोदाम तक पहुंचने के बाद भीमताल होते हुए ओखलकांडा के लिए सड़क मार्ग उपलब्ध है। अंतिम पड़ाव के बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए कुछ किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। यह चढ़ाई जितनी शरीर की परीक्षा लेती है, उतनी ही मन को भी भीतर की ओर मोड़ देती है। हर कदम के साथ सांसें तेज होती हैं, पर मन हल्का और शांत होता चला जाता है। रास्ते में बदलते दृश्य, घाटियों का विस्तार और आकाश की निकटता यात्रा को अविस्मरणीय बना देती है।

स्थानीय लोग इस मंदिर को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले यहां आशीर्वाद लेना सामान्य परंपरा है। विवाह, गृह प्रवेश, शिक्षा आरंभ या किसी नई योजना की शुरुआत—हर अवसर पर देवगुरु बृहस्पति का स्मरण किया जाता है। उनका विश्वास है कि गुरु की कृपा के बिना जीवन में संतुलन और स्थिरता संभव नहीं।

देवगुरु पर्वत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सादगी है। यहां न भव्य बाजार हैं, न चकाचौंध भरी व्यवस्थाएं। केवल प्रकृति, श्रद्धा और मौन है। शायद यही मौन इस स्थान की सबसे बड़ी शिक्षा है। यह मौन सिखाता है कि सच्चा ज्ञान शोर में नहीं, बल्कि शांति में प्रकट होता है। देवगुरु बृहस्पति की यह तपस्थली आज भी उसी उद्देश्य को निभा रही है—मनुष्य को विवेक, संतुलन और सत्य के मार्ग पर ले जाने का उद्देश्य। यहां से लौटते समय व्यक्ति केवल दर्शन नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव अपने साथ लेकर लौटता है, जो लंबे समय तक उसके जीवन को दिशा देता रहता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन से आद्यशक्ति धाम अंबाजी का होलिस्टिक तथा फ्युचरिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अंबाजी में मुख्य मंदिर, गब्बर तथा मानसरोवर को जोड़ने वाला 'शक्ति कॉरिडोर' के निर्माण में प्रथम चरण के 950 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया

▸▸ प्रथम चरण के निर्माण में मल्टी लेवल पार्किंग, अंडर पास रोड, यात्री निवास, पाथ-वे, शक्ति पथ, शक्ति कॉरिडोर- एम्फीथियेटर सहित अनेक सुविधाएं

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को आद्यशक्ति धाम अंबाजी में कुल 1,632 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च से निर्मित होने वाले अंबाजी कॉरिडोर के प्रथम चरण के 950 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास सम्पन्न किया।

आगामी 25 वर्षों के यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अंबाजी में 'शक्ति कॉरिडोर' के लिए 1,632 करोड़ रुपए का विजनरी मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अंबाजी कॉरिडोर के प्रथम चरण के जिन कार्यों का शिलान्यास किया है, उससे आने वाले दिनों में यात्रियों को मल्टी लेवल पार्किंग, अंडरपास रोड, यात्री निवास, पाथ-वे, दिव्य दर्शन चौक, शक्तिपीठ, एम्फीथिएटर और लाइट एंड साउंड शो सहित अनेक पर्यटन सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस गौरवशाली समारोह की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि आद्यशक्ति के परम उपासक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में आद्यशक्ति पीठ अंबाजी का होलिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक विकास हो रहा है।

मुख्यमंत्री के साथ इन बहुविध विकास कार्यों के शिलान्यास अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य : प्रवीणभाई माळी, डॉ. जयरामभाई गामित, कमलेशभाई पटेल, स्वरूपजी ठाकोर तथा बनासकांठा जिले के विधायक एवं पदाधिकारी भी शामिल हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आद्यशक्ति की आराधना और 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' से लेकर देश के तीर्थ स्थलों के नवीनीकरण के कार्य 'विकास भी विरासत भी' के मंत्र के साथ प्रारंभ किए हैं।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, केदारनाथ और बैजनाथ धाम जैसे पवित्र स्थलों के विकास को नई पहचान मिली है। उनके नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और पावागढ

में पांच सौ वर्षों बाद ध्वजारोहण जैसी ऐतिहासिक घटनाएं भी सम्पन्न हुई हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 51 शक्तिपीठों में विशिष्ट स्थान रखने वाले अंबाजी धाम के विकास के लिए प्रधानमंत्री का विजन साकार हो रहा है। हर वर्ष 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव का सफल आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु माता जी के दर्शन का लाभ लेते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में आयोजित परिक्रमा महोत्सव में पांच लाख से अधिक भक्तों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ आगामी 25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंबाजी का विजनरी मास्टर प्लान तैयार किया गया है

▸▸ प्रधानमंत्री ने पवित्र तीर्थ क्षेत्र 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' से लेकर देश के तीर्थ स्थलों का नवीनीकरण 'विकास भी विरासत भी' के मंत्र से साकार किया है

▸▸ अंबाजी–तारंगा–रेल परियोजना से आसान कनेक्टिविटी और स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी

श्री पटेल ने कहा कि तीर्थ स्थलों के विकास को पर्यटन से जोड़ने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए अंबाजी में गब्बर स्थल पर देश का सबसे बड़ा लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया है तथा परिक्रमा पथ और सांस्कृतिक विलेज जैसे प्रकल्पों से यात्रियों को नई सुविधाएं मिल रही हैं ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अंबाजी–तारंगा रेल परियोजना से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसके परिणामस्वरूप यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

उन्होंने जोड़ा कि गुजरात पवित्र तीर्थस्थल विकास बोर्ड द्वारा राज्य के विभिन्न तीर्थ स्थलों में अब तक करोड़ों के विकास कार्य पूर्ण किए गए हैं और आने वाले समय में और अधिक विकास कार्यों की योजना बनाई गई है।

इस अवसर पर मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पवित्र तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार और विकास के लिए जो पहल की है, उसे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल दृढ़ता से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आस्था, संस्कृति और शक्ति का जहां त्रिवेणी संगम होता है, ऐसे अंबाजी धाम के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार संपूर्ण कटिबद्ध है। सरकार की यह योजना इतनी भव्य और दूरदर्शी है कि अंबाजी की इस नई विकास यात्रा को आने वाली पीढ़ियां युगों तक याद रखेंगी।

मंत्री श्री जयरामभाई गामित ने कहा कि अंबाजी शक्तिपीठ में हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा के महा मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की इस अटूट आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 1,632 करोड़ रुपए के मेगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट के माध्यम से अंबाजी का कायापलट किया जाएगा। इन ऐतिहासिक विकास कार्यों से श्रद्धालुओं को अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी और साथ ही स्थानीय स्तर पर नए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित होंगे, जो बनासकांठा जिले के आर्थिक विकास को नई गति देंगे।

इस कार्यक्रम में पर्यटन सचिव श्री कुलदीप आर्या, गुजरात पवित्र तीर्थस्थल विकास बोर्ड के सदस्य सचिव श्री रमेश मेरजा, जिला कलेक्टर श्री मिहिर पटेल, जिला विकास अधिकारी श्री एम. जे. दवे, अंबाजी सरपंच सहित विभिन्न अधिकारी, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा दस जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए विभिन्न गंतव्यों के बीच 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित किए गए हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 09207/09208 बांद्रा टर्मिनस – भावनगर साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 09207 बांद्रा टर्मिनस – भावनगर साप्ताहिक स्पेशल को 27 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09208 भावनगर ▸▸ बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 26 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

2. ट्रेन संख्या 09415/09416 बांद्रा टर्मिनस – गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 09415 बांद्रा टर्मिनस – गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल को 26 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09416 गांधीधाम ▸▸ बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 26 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

3. ट्रेन संख्या 09055/09056 बांद्रा टर्मिनस – उधना स्पेशल
ट्रेन संख्या 09055 बांद्रा टर्मिनस – उधना स्पेशल को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09056 उधना – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

4. ट्रेन संख्या 09037/09038 बांद्रा टर्मिनस – भुज द्वि-साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 09037 बांद्रा टर्मिनस – भुज साप्ताहिक स्पेशल को 28 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09038 भुज – बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 29 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

5. ट्रेन संख्या 09009/09010 बांद्रा टर्मिनस – भुज साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 09009 बांद्रा टर्मिनस – भुज साप्ताहिक स्पेशल को 29 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09010 भुज – बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 30 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

6. ट्रेन संख्या 09011/09012 बांद्रा टर्मिनस – भुज साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 09011 बांद्रा टर्मिनस – भुज साप्ताहिक स्पेशल को 31 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09012 भुज – बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 25 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

7. ट्रेन संख्या 09017/09018 बांद्रा टर्मिनस – वेरावल साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 09017 बांद्रा टर्मिनस – वेरावल साप्ताहिक स्पेशल को 29 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09018 वेरावल ▸▸ बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 30 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

8. ट्रेन संख्या 09035/09036 बांद्रा टर्मिनस – उधना द्वि-साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 09035 बांद्रा टर्मिनस – उधना साप्ताहिक स्पेशल को 28 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09036 उधना – बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 27 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

9. ट्रेन संख्या 09561/09562 बांद्रा टर्मिनस – ओखा साप्ताहिक स्पेशल
ट्रेन संख्या 09561 बांद्रा टर्मिनस – ओखा साप्ताहिक स्पेशल को 25 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09562 ओखा – बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल को 31 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

10. ट्रेन संख्या 09215/09216 भावनगर – गांधीग्राम डेली स्पेशल (अनारक्षित)
ट्रेन संख्या 09215 गांधीग्राम – भावनगर डेली अनारक्षित स्पेशल को 31 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09216 भावनगर ▸▸ गांधीग्राम डेली अनारक्षित स्पेशल को 31 मार्च, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

उपर्युक्त सभी आरक्षित ट्रेनों के विस्तारित फेरों की बुकिंग 08 फरवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव के समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने गुजरात के पहले ग्रीन रेलवे स्टेशन – एकतानगर का किया दौरा

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने दिनांक 07 फरवरी 2026 को भारत के सबसे सुंदर और आधुनिक रेलवे स्टेशनों में से एक तथा गुजरात के पहले "ग्रीन रेलवे स्टेशन" एकता नगर का दौरा किया।

श्री कुमार ने रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर स्वच्छता, आधुनिक सुविधाओं एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री कुमार को इस खंड पर चल रही परियोजनाओं और मंडल की उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि एकता

नगर स्टेशन पर ट्रेन परिचालन क्षमता को विस्तार देते हुए एक अतिरिक्त लूप लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। डभोई और एकतानगर रेल खंड में कैटल रन ओवर की घटना को रोकने के लिए मैटल क्रैश बैरियर लगाने का कार्य प्रगति पर है। इससे इस रेल खंड में ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में सुधार होगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विज़न को साकार करते हुए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत गोधरा स्टेशन का कायाकल्प हो गया है। जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जायेगा। इसी प्रकार प्रतापनगर और डभोई स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास कार्य प्रगति पर है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतापनगर और डभोई स्टेशन पर 12 मीटर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण अंतिम चरण में है। इस रेल खंड के कुंदेला और तिलकवाड़ा स्टेशनों को B स्टेशन में परिवर्तित किया गया है, जिससे परिचालन क्षमता के सुधार के साथ साथ सैक्शन कैपिसिटी में वृद्धि संभव होगी।

एकतानगर स्टेशन पर निरीक्षण के बाद महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने आज वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के साथ एकता नगर - प्रतापनगर खंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने रेल पटरियों की सुरक्षा और परिचालन दक्षता की समीक्षा की।

महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने अपने इस दौरे में वडोदरा मंडल के अधिकारियों से मंडल कार्यालय में संवाद भी किया और मंडल के अधिकारियों का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने वर्क साइट विशेषकर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य में संरक्षा को विशेष प्राथमिकता देने के साथ साथ कैपेसिटी एनहांसमेंट, बिज़नेस डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में मजबूती से काम करने पर जोर दिया। श्री कुमार ने मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के नेतृत्व और उनकी अधिकारिओं की उपलब्धियों और उनके पारस्पर सहयोग एवं टीम वर्क की सराहना भी की।

यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, लापरवाही ने ली छह जानें

आय फाइनेंस का आईपीओ बाजार में उतरने को तैयार, एंकर निवेशकों से 454.5 करोड़ की मजबूत शुरुआत

नई दिल्ली। नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आय फाइनेंस लिमिटेड ने अपने प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से पहले एंकर निवेशकों से 454.5 करोड़ रुपये जुटाकर बाजार में मजबूत एंट्री का संकेत दे दिया है। कंपनी ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में बताया कि एंकर इन्वेस्टर्स को 129 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इक्विटी शेयर अलॉट किए गए हैं। यह आईपीओ 9 फरवरी को आम निवेशकों के लिए खुलेगा और 11 फरवरी तक इसमें बोली लगाई जा सकेगी। बाजार जानकारों का मानना है कि एंकर निवेशकों की मजबूत भागीदारी से निवेशकों के बीच इस इश्यू को लेकर सकारात्मक माहौल बन सकता है।

कंपनी के मुताबिक एंकर निवेशकों को कुल 3,52,32,558 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। इनमें से 76,74,560 इक्विटी शेयर दो घरेलू म्यूचुअल फंड्स की चार अलग-अलग स्कीमों को दिए गए हैं। एंकर निवेशकों की सूची में देश और विदेश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के नाम शामिल हैं, जिनमें न्यूयॉर्क स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट सिस्टम, सोसाइटे जेनरल, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बीएनपी पारिबा फाइनेंशियल मार्केट्स, बे पॉन्ड पार्टनर्स और इथान क्रीक मास्टर इन्वेस्टर्स (केमैन) जैसे बड़े वैश्विक निवेशक शामिल हैं। इन नामों की मौजूदगी से कंपनी के कारोबारी मॉडल और भविष्य की संभावनाओं पर संस्थागत निवेशकों के भरोसे को बल मिलता है।

आय फाइनेंस लिमिटेड ने अपने आईपीओ के लिए 122 रुपये से 129 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी का लक्ष्य इस इश्यू के जरिए पूंजी जुटाकर अपने लोन पोर्टफोलियो को और मजबूत करना, डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाना और देश के उन क्षेत्रों में अपनी पहुंच का विस्तार करना है, जहां औपचारिक बैंकिंग सेवाएं सीमित हैं। कंपनी मुख्य रूप से किफायती आवास वित्त, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण तथा निम्न और मध्यम आय वर्ग के ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा समय में एनबीएफसी सेक्टर निवेशकों की नजर में फिर से आकर्षण का केंद्र बन रहा है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो संतुलित जोखिम प्रबंधन और स्थिर ग्रोथ मॉडल पर काम कर रही हैं। आय फाइनेंस लिमिटेड ने पिछले कुछ वर्षों में अपने एसेट क्वालिटी, कलेक्शन एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी आधारित लेंडिंग सिस्टम पर खासा जोर दिया है, जिसका असर इसके वित्तीय प्रदर्शन में भी देखने को मिला है। एंकर निवेशकों की भागीदारी को इसी भरोसे का संकेत माना जा रहा है।

आईपीओ के खुलने के साथ ही खुदरा निवेशकों, गैर-संस्थागत निवेशकों और योग्य संस्थागत खरीदारों की नजर इस इश्यू पर रहेगी। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यदि समग्र बाजार का रुझान सकारात्मक बना रहता है, तो इस आईपीओ को अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। निवेशकों को हालांकि कंपनी के बिजनेस मॉडल, जोखिम कारकों और वित्तीय स्थिति का अध्ययन कर ही निवेश निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है।

गुजरात के गांधीधाम–आदिपुर रेलखंड का चौहरीकरण, गति और व्यापार को मिलेगा नया बल

क्षमता वृद्धि, सुगम परिचालन और क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति की दिशा में अहम कदम

10 फरवरी को 120 किमी प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल, रेलवे ट्रैक से दूर रहने की अपील पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मण्डल के गांधीधाम-आदिपुर (10.69 किमी) रेल सेक्शन के बीच चौहरीकरण (Quadrupling) परियोजना के अंतर्गत तीसरी और चौथी लाइन कार्य पूर्ण हो गया है। 9 व 10 फरवरी 2026 को रेल संरक्षा आयुक्त (CRS), पश्चिम सर्कल द्वारा संरक्षा निरीक्षण किया जायेगा तथा 10 फरवरी 2026 को 120 किमी प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल किया जाएगा। स्थानीय निवासियों से विशेष अनुरोध है कि वे रेलवे ट्रैक से दूर रहे और रेलवे लाइन पार न करें। अहमदाबाद मंडल अपने रेल नेटवर्क को अधिक सक्षम, सुरक्षित और भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में गुजरात के गांधीधाम–आदिपुर रेलखंड के बीच चौहरीकरण तथा आदिपुर स्टेशन पर 'वाई' कनेक्शन देने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। यह परियोजना कच्छ क्षेत्र में बढ़ती रेल मांग को पूरा करने और बंदरगाह आधारित माल यातायात को सुचारु बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएँ:

▸▸ ट्रैक लिंकिंग: 17 किलोमीटर

▸▸ छोटे ब्रिज : 8

▸▸ अर्थवर्क (मिट्टी कार्य): 2.60 लाख घन मीटर

▸▸ आदिपुर स्टेशन पर सिग्नल व टेलीकॉम (S&T) एवं ऑपरेटिंग कंट्रोल (OC) बिल्डिंग का निर्माण

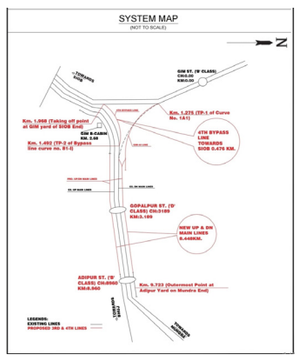

▸▸ चौथी लाइन सहित समस्त सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन

▸▸ इस सेक्शन के बीच आने वाले एकमात्र गोपालपुर रेलवे स्टेशन का छायापुरी स्टेशन की तर्ज पर आधुनिक स्टेशन भवन का निर्माण।

▸▸ गांधीधाम बी केबिन में प्रमुख यार्ड रीमॉडलिंग कार्य किया गया है, जिसमें 16 नए प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग डाले गए हैं।

▸▸ आदिपुर स्टेशन पर भी प्रमुख यार्ड रीमॉडलिंग कार्य किया गया है, जिसमें 21 नए प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग डाले गए हैं, साथ ही 1 लूप लाइन भी शामिल है।

परियोजना का महत्व:

गांधीधाम–आदिपुर ब्रॉडगेज रेलखंड एक महत्वपूर्ण माल ढुलाई खंड है। इस मार्ग से कांडला व मुंद्रा बंदरगाह, भुज, वायोर और अन्य क्षेत्रों का आयात–निर्यात माल देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचता है। वर्तमान में यह खंड अत्यधिक व्यस्त (ओवरसैचुरेटेड) है जिससे परिचालन पर दबाव बना रहता है। इन परिचालन बाधाओं को कम करने के लिए दो अतिरिक्त लाइनों की आवश्यकता थी।

भुज, वायोर और हाजीपीर क्षेत्रों से नमक और सामान्य माल भी इसी मार्ग से देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है। मुंद्रा बंदरगाह की बढ़ती क्षमता को देखते हुए भविष्य में माल यातायात और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में गांधीधाम–आदिपुर के बीच चौहरीकरण से भीड़ कम होगी और मालगाड़ियों का संचालन बेहतर होगा। यह परियोजना कच्छ क्षेत्र के विकास को भी गति देगी।

▸▸ यह सेक्शन अहमदाबाद मंडल में सबसे अधिक GMT (Gross Million Tonnes) लोडिंग वाला है। इस क्षेत्र से प्रति वर्ष 70 से अधिक जीएमटी लोडिंग होती हैं। चौहरीकरण (Quadrupling) से इस सेक्शन की लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे ट्रेनों का परिचालन अधिक सुचारु, समयनिष्ठ और सुरक्षित बनेगा। लाइन क्षमता बढ़ने से यात्री ट्रेनों की समयपालनता सुधरेगी, पीक समय में भी संचालन आसान होगा और नई ट्रेनों या अतिरिक्त फेरों की संभावना बढ़ेगी। यात्रियों को अधिक भरोसेमंद और आरामदायक यात्रा मिलेगी।

▸▸ गांधीधाम–आदिपुर खंड पश्चिम रेलवे का एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्ग है, जो बंदरगाहों, उद्योगों और राष्ट्रीय रेल नेटवर्क को जोड़ता है। इस मार्ग पर माल और यात्री दोनों ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है। तीसरी और चौथी लाइन बनने से लाइन क्षमता बढ़ेगी और ट्रेनों का संचालन बिना रुकावट के हो सकेगा।

▸▸ नवनिर्मित गोपालपुर नये रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद की ओर से आने वाली गाड़ियों को भुज जाने के लिए गांधीधाम में जाकर इंजन रिवर्सल करने की आवश्यकता नहीं होगी और जिससे यात्री गाड़ियां का 20 मिनट समय बचेगा।

▸▸ आदिपुर स्टेशन पर 'वाई' कनेक्शन से ट्रेनों को दिशा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय और ईंधन की बचत होगी, संचालन आसान होगा।

▸▸ इस परियोजना से कांडला और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों से जुड़े कंटेनर, पेट्रोलियम, उर्वरक, खाद्यान्न और अन्य माल के परिवहन में तेजी आएगी। मालगाड़ियों का टर्नअराउंड समय कम होगा, वैगनों का बेहतर उपयोग होगा और लॉजिस्टिक लागत घटेगी, जिससे उद्योगों को लाभ मिलेगा और निर्यात–आयात को बढ़ावा मिलेगा।

▸▸ यह परियोजना कच्छ क्षेत्र के औद्योगिक विकास को मजबूती देगी, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ाएगी तथा निवेश के लिए अच्छा माहौल बनाएगी।

गांधीधाम–आदिपुर चौहरीकरण और 'वाई' कनेक्शन परियोजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो रेल ढांचे को मजबूत करेगी और कच्छ क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान देगी।

भूपेंद्र दादा ने बनासकांठा की बेटी से किया हुआ वचन निभाया

प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया कार्य मंत्र 'जो कहना उसे करना' का मुख्यमंत्री ने साकार किया

▸▸ बेटी साम्या की एक भावना और मुख्यमंत्री का एक वचन : बनासकांठा में साकार हुआ सहज संवाद

▸▸ "दादा, आप आएंगे न?" - बेटी साम्या की भावना को मुख्यमंत्री ने दिया मान

▸▸ वीडियो संवाद में दिए गए वचन से स्कूल यात्रा तक : साम्या और मुख्यमंत्री का भावनात्मक सहज संवाद

▸▸ "पढ़-लिखकर कलेक्टर बनना" : मुख्यमंत्री का आशीर्वाद

▸▸ आज मेरा और मेरी स्कूल का सपना पूरा हुआ : साम्या प्रजापति

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अक्सर अपनी वयोवृद्ध वात्सल्यता एवं मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते रहे हैं। ऐसा ही एक भावनात्मक प्रसंग बनासकांठा जिले के पीएम श्री उत्तमपुरा (डांगिया) अनुपम प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिला।

ता. 28/04/2025 को आयोजित एक वीडियो संवाद के दौरान कक्षा-1 में पढ़ने वाली बेटी साम्या प्रजापति ने सहजता से मुख्यमंत्री से पूछा था, "दादा, आप हमारी स्कूल में कब आएंगे?"

इस मासूम प्रश्न पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वयोवृद्ध स्नेहपूर्ण उत्तर देते हुए कहा था, "मैं जब भी वहां आऊंगा तब जरूर तुमसे मिलने आऊंगा।"

मुख्यमंत्री ने उस समय जो बात कही थी वह उनके मन में थी और इसी कारण उन्होंने बनासकांठा में होने वाले कार्यक्रम

में इस बेटी के गांव की स्कूल की भेंट अवश्य करने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का शनिवार को अंबाजी कॉरिडोर के शिलान्यास अवसर पर बनासकांठा के दौरे का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में जाने से पहले उत्तमपुरा-डांगिया गांव की स्कूल की यात्रा का आयोजन किया।

मुख्यमंत्री ने पहले दिए गए वचन को पूरा करने के लिए बेटी साम्या की भावना का सम्मान करते हुए पीएम श्री उत्तमपुरा (डांगिया) अनुपम प्राथमिक विद्यालय की व्यक्तिगत रूप से भेंट की। मुख्यमंत्री ने स्कूल के विद्यार्थियों के साथ आत्मीय और सहज संवाद किया तथा उनके अभ्यास, स्कूल परिसर और शिक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर बेटी साम्या ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि, "मैंने दादा से कहा था कि आप हमसे मिलने आएंगे न दादा ने बात याद रखी और आज मेरा और मेरी स्कूल का सपना पूरा कर दिया।"

साम्या ने मुख्यमंत्री के सामने श्लोक पाठ किए। उसका प्रतिसाद देते हुए मुख्यमंत्री ने बेटी को आशीर्वाद देते हुए कहा, "तुम पढ़-लिखकर बड़ी होकर कलेक्टर बनना और फिर मुझसे मिलने आना।"

बेटी साम्या ने भी दृढ़ विश्वास के साथ दादा को वचन दिया कि, "मैं बड़ी होकर आपसे जरूर मिलने आऊंगी।"

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की इस सहजता और मानवीय संवेदनशीलता से स्कूल परिवार तथा राज्यभर के एसएमसी सदस्यों में भी विशेष आनंद की भावना छा गई।

इस भावनात्मक अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी, स्कूल के शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीय अग्रणी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अंबाजी में मां अंबा के दर्शन कर राज्य की शांति, समृद्धि तथा कल्याण के लिए प्रार्थना की

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अंबाजी में जगत जननी मां अंबा के पावन दर्शन कर मां के चरणों में शीश झुकाए।

मुख्यमंत्री ने राज्य की शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री अंबाजी कॉरिडोर के प्रथम चरण के कामों के शिलान्यास के लिए अंबाजी की यात्रा पर थे, उस दौरान उन्होंने अंबाजी मंदिर में विधि-विधानपूर्वक पूजा अर्चना की।

पश्चिम रेलवे

इलेक्ट्रिफिकेशन और वायरिंग का काम

Dy.CEE/C/RTM ने टेंडर नोटिस नंबर: EL-C-RTM-2025-07-T तारीख: 03.02.2026 जारी किया है। काम का नाम: दाहोद-इंदौर नई लाइन प्रोजेक्ट के संबंध में टिही-धार सेक्शन में टिरला, अमझेरा और सरदारपुर स्टेशनों और टिही, पीथमपुर, सगोर और धार स्टेशनों पर स्टाफ क्वार्टर के स्टेशन और सर्विस बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, कवरिंग शेड आदि के इलेक्ट्रिफिकेशन और वायरिंग का काम। अनुमानित मूल्य: ₹ 5,18,35,422/- बिड डिपॉज़िट: ₹ 4,09,200/- ऑनलाइन बिडिंग शुरू होने की तारीख: 10.02.2026. टेंडर बंद होने की तारीख: 24.02.2026 को 15.00 बजे तक।अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं।

1084

हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly

708 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 11,301 करोड़ का बजट, टैक्स में लगातार तीसरे साल राहत

सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट में स्टैंडिंग कमिटी अध्यक्ष राजन पटेल ने म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत 10,593 करोड़ रुपये के ड्राफ्ट बजट में 708 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करते हुए कुल बजट आकार 11,301 करोड़ रुपये कर दिया है। यह सूरत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। आगामी लोकल बॉडी चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में मिडिल क्लास, महिलाओं और सीनियर सिटिज़न्स को सीधे राहत देने वाली कई योजनाओं की घोषणा की गई है।

महंगाई के दौर में सूरत के नागरिकों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि नगर निगम ने लगातार तीसरे वर्ष किसी भी प्रकार के टैक्स या रेट्स में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। भारी बजट के बावजूद टैक्स स्थिर रखना सत्ताधारी दल की राजनीतिक इच्छाशक्ति और चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्ज और अन्य म्युनिसिपल रेट्स में कोई अतिरिक्त बोझ आम जनता पर नहीं डाला जाएगा।

इस बजट में महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए विधवाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों को प्रॉपर्टी टैक्स से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली विधवाएं अपना बेनिफिशियरी कार्ड दिखाकर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकेंगी। इस निर्णय से शहर की बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। सीनियर सिटिज़न्स के लिए भी बजट में बड़ी राहत दी गई है। अब सूरत के वरिष्ठ नागरिक बीआरटीएस बसों में पूरी तरह मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए सिविक सेंटर से पास बनवाना होगा। नगर निगम का मानना है कि इससे बुज़ुर्गों की आवाजाही आसान होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग भी बढ़ेगा।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने 'सूरती हाट बाज़ार' शुरू करने का ऐलान किया है। यह बाज़ार महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स और स्थानीय कारीगरों को उनके उत्पाद बेचने के लिए स्थायी मंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही सफ़ाई से जुड़ी गतिविधियों के लिए महिलाओं को निःशुल्क दुकानें उपलब्ध कराने की योजना भी बजट में शामिल की गई है।

शहर के विकास कार्यों को गति देने के लिए कमिश्नर के बजट में 656 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है। इस राशि का उपयोग नए फ्लाईओवर, सड़कों के नवीनीकरण, ड्रेनेज सिस्टम को मज़बूत करने और स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में किया जाएगा।

धार्मिक संस्थाओं के लिए भी पहली बार 25 करोड़ रुपये की ग्रांट का प्रावधान किया गया है, जिससे धार्मिक स्थलों पर पानी, सड़क, पेवर ब्लॉक और सोलर पैनल जैसी सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा। वहीं शहर की करीब 1160 रेजिडेंशियल सोसाइटियों को दी जाने वाली सैनिटेशन ग्रांट की दर बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी गई है, ताकि सोसाइटियां स्वच्छता के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें।

नागरिक सुविधाओं के विस्तार के तहत शहर के सभी 30 चुनावी वार्डों में आधार कार्ड सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे लोगों को ज़ोन ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सरथाना नेचर पार्क के आधुनिकीकरण के लिए विशेष बजट रखा गया है। पिछले तीन वर्षों में 25 लाख से अधिक लोग इस पार्क का दौरा कर चुके हैं और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा वाला बनाने की योजना है।

शिक्षा क्षेत्र में भी बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है। एजुकेशन कमिटी के तहत 362 स्कूलों के लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को 15 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसके अलावा 20 नए स्कूलों में हाई-टेक लैब स्थापित की जाएंगी, जिससे 15,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा। एआर-वीआर आधारित शिक्षा के लिए 1.50 करोड़ रुपये और स्कूलों में कंप्यूटर, प्रिंटर व फोटोकॉपियर के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर में 250 नए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। रक्षा बंधन और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को सिटी बस और बीआरटीएस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए एग्ज़िबिशन और सेल का आयोजन भी किया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में स्मीयर हॉस्पिटल में अत्याधुनिक ब्लड बैंक और एफेरेसिस यूनिट के लिए 2 करोड़ रुपये तथा सेंट्रल लेबोरेटरी में मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक और एडवांस्ड पैथोलॉजी सुविधाओं के लिए 2.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पुना-सिमाडा और सरथाना क्षेत्रों में नए हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल विकसित करने की योजना भी बजट का हिस्सा है। इसके साथ ही रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट, सिंगनपुर से कॉजवे तक मॉडर्न रोड नेटवर्क और लैंडस्केपिंग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

कुल मिलाकर, यह बजट टैक्स में राहत, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और चुनावी वर्ष में आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का संतुलित पैकेज माना जा रहा है।

बिहार में अप्रैल 2026 से शुरू होगी जनगणना,45 दिनों में पूरा होगा घर-घर सर्वे का काम

पटना। बिहार में होने वाली जनगणना को लेकर राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से तारीखों की घोषणा कर दी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया कि बिहार में जनगणना का काम दो फेजों में किया जाएगा। इसकी कुल अवधि करीब 45 दिन होगी। यह जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनगणना विभाग को सौंपी गई है।

जनगणना का पहला चरण अप्रैल 2026 में शुरू होगा। इस दौरान मकानों और घरों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। सिन्हा ने बताया कि यह चरण 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। इसमें घर-घर जाकर लोगों से जुड़ी पूरी जानकारी ली जाएगी। यह काम 2 मई से 31 मई 2026 तक पूरा किया जाएगा।

इस सर्वे के दौरान हर परिवार की स्थिति, घर में उपलब्ध सुविधाएं और अन्य बुनियादी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होगी और लोगों द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी जानकारी का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।

इस बार की जनगणना को खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें जाति से जुड़ी जानकारी भी शामिल की जाएगी। केंद्र सरकार पहले ही संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि जनगणना हमेशा दो चरणों में होती है। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसी चरण में जाति से संबंधित सवाल भी जोड़े जाएंगे, ताकि देश और राज्य की सामाजिक संरचना की साफ तस्वीर सामने आ सके। विभाग ने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग भविष्य की योजनाओं, विकास कार्यों और नीतिगत फैसलों में किया जाएगा। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों और वर्गों को किस तरह की सहायता की जरूरत है।

केशोद में AAP विधायक गोपाल इटालिया और फ्रंटल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण राम की विशेष उपस्थिति में "किसान संवाद कार्यक्रम" आयोजित किया गया

▸▸ एक प्रवीणभाई को जेल में डालोगे तो 500 प्रवीणभाई तैयार होंगे: गोपाल इटालिया

प्रवीणभाई की अग्नि परीक्षा ली गई और वे पूरे अंकों के साथ पास हुए: गोपाल इटालिया

▸▸ आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेज भी भाजपा नेताओं की तरह ही सोचते होंगे: गोपाल इटालिया

▸▸ भाजपा नेताओं को भी यह भ्रम है कि अगर AAP के नेताओं को जेल में डाल देंगे तो गुजरात में भाजपा ही चलती रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है: गोपाल इटालिया

▸▸ पहली बार भाजपा के सामने खड़े होने वाले युवा मैदान में उतरे हैं और इसी वजह से अब भाजपा वाले परेशान हो गए हैं: गोपाल इटालिया

▸▸ पूरे गुजरात का भरोसा अब AAP पार्टी पर है: गोपाल इटालिया

▸▸ हम पर जो झूठे केस किए गए, वह गुजरात के किसानों को पसंद नहीं आए: प्रवीण राम

▸▸ मैं इकोज़ोन मुद्दे पर, घेड मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर आवाज उठाता हूं, इसी वजह से मुझे जेल में डाला गया: प्रवीण राम

▸▸ जो लोग वीडियो में पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों में से एक पर भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई: प्रवीण राम

▸▸ हडदड में भाजपा द्वारा किया गया षड्यंत्र था: प्रवीण राम

▸▸ मैंने किसानों से बैठकर रहने को कहा और शांति की अपील भी की: प्रवीण राम

▸▸ जिन लोगों ने हमें जेल में डाला, उन्होंने हमें और मजबूत किया: प्रवीण राम

▸▸ घेड और किसानों सहित पिछली सभी लड़ाइयां फिर से शुरू होंगी: प्रवीण राम

▸▸ अहमदाबाद/जूनागढ़/सुरेंद्रनगर/बोटाद/राजकोट/अमरेली/देवभूमि द्वारका/गिर सोमनाथ/पोरबंदर/गुजरात

आम आदमी पार्टी के किसान नेता और फ्रंटल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण राम 108 दिनों की जेलवास के बाद बाहर आए हैं और किसानों सहित पूरे गुजरात के लोगों के लिए अपनी मजबूत आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया के साथ किसान नेता प्रवीण राम ने आज केशोद में "किसान संवाद" कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, किसान, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विधायक गोपाल इटालिया ने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज भी भाजपा नेताओं की तरह ही सोचते होंगे कि "अगर आजादी की बात लेकर निकलने वालों को जेल में डाल दिया जाए तो आजादी की बात ही बंद हो जाएगी।" इसी सोच के साथ अंग्रेजों ने हमारे देश के कई महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला, फिर भी आजादी आई। भाजपा नेताओं को भी यह भ्रम है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल देंगे तो गुजरात में भाजपा ही चलती रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप एक प्रवीण राम को जेल में डालोगे तो 500 प्रवीण राम तैयार होंगे, अगर आप एक राजू करपड़ा को जेल में डालोगे तो 500 राजू करपड़ा तैयार होंगे।

आगे विधायक गोपाल इटालिया ने कहा कि अब तक भाजपा और कांग्रेस के नेता एक-दूसरे का काम करते थे और अंदरखाने पार्टी बदलते रहते थे, जिसके कारण जनता का कोई काम नहीं होता था। उन्होंने कभी भी गुजरात के आम लोगों और खासकर किसानों की आवाज नहीं सुनी। लेकिन अब गुजरात में और देश में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई और एक तरफ से ईसुदानभाई आए, एक तरफ से मैं आया, एक तरफ से प्रवीणभाई आए, एक तरफ से चैतरभाई आए और इस तरह कई लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े और भगवान के आशीर्वाद से गुजरात में आम आदमी पार्टी का मजबूत काम हुआ। इसलिए पूरे गुजरात की उम्मीद और भरोसा आम आदमी पार्टी पर टिका है। अब तक भाजपा को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब पहली बार भाजपा के सामने खड़े होने वाले युवा मैदान में आए हैं और इसी वजह से भाजपा वाले परेशान हो गए हैं। और अगर आगे भी गुजरात की जनता का आशीर्वाद मिला तो भाजपा वाले हाथ में भी नहीं आएंगे।

इसके बाद आम आदमी पार्टी के किसान नेता प्रवीण राम ने अपने संबोधन में कहा कि 108 दिनों की जेलवास के दौरान केशोद की जनता

सहित पूरे गुजरात की जनता ने जिस तरह मुझे और मेरे परिवार को समर्थन दिया, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। हम पर जो झूठे केस किए गए, वह गुजरात के किसानों को पसंद नहीं आए। मुझे किसी व्यक्तिगत लड़ाई के कारण जेल में नहीं डाला गया, बल्कि मैं इकोज़ोन की लड़ाई लड़ता हूं, घेड मुद्दे पर लड़ाई लड़ता हूं, किसानों की आवाज उठाता हूं, इसी वजह से मुझे जेल में डाला गया। उन्हें लगा कि हमें जेल में डालकर वे हमें कमजोर कर देंगे, लेकिन मैं सभी से कहना चाहता हूं कि हमें जेल में डालकर आप लोगों ने हमें और मजबूत किया है और भगवान करे कि आप लोग सौ साल जिएं।

इसके बाद किसान नेता प्रवीण राम ने हडदड में हुई घटना के बारे में बात करते हुए कहा कि हडदड गांव में मैंने अपनी बात पूरी की और राजूभाई करपड़ा ने भी अपनी बात पूरी की और बस कार्यक्रम खत्म होने ही वाला था। उसी समय पुलिस आती है और मैंने किसानों से बैठकर रहने को कहा तथा शांति की अपील की। लेकिन पुलिस वापस चली जाती है और कुछ मिनट बाद फिर लौट आती है और हमने फिर से लोगों से बैठने की अपील की। तीसरी बार जब पुलिस आई तो हेलमेट और लाठियों के साथ आई। इसके बाद पुलिस भीड़ में घुस गई। वहां जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उनकी विवेकबुद्धि कहां चली गई? क्या पुलिस ने उकसाया नहीं? और भी गंभीर बात यह है कि जिन लोगों को उन्होंने भेजा, उनमें से कुछ ने पत्थरबाजी की, जिनमें भाजपा के लोग भी थे। इस पूरी घटना के बाद जिन 85 लोगों पर पुलिस शिकायत दर्ज की गई, उनमें से एक भी व्यक्ति पत्थर फेंकता हुआ नहीं था। इन 85 लोगों के पत्थर फेंकने का एक भी वीडियो पुलिस के पास नहीं था, तो फिर पुलिस ने इन लोगों को कैसे गिरफ्तार किया? दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग वीडियो में पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर एक भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि यह भाजपा द्वारा किया गया षड्यंत्र था।

वडोदरा में अनुसूचित जाति सशक्तिकरण को मिली नई गति

वडोदरा। अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वांगीण उत्थान और सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता वडोदरा जिले में लगातार ठोस रूप लेती दिखाई दे रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत अनुसूचित जाति कल्याण कार्यालय, वडोदरा द्वारा जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ दूर-दराज और पिछड़े इलाकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सुनियोजित और प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की यह पहल केवल सहायता राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले छह महीनों, यानी अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 की अवधि के दौरान वडोदरा जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित विभिन्न शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट रही है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के मार्ग में किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे बिना बाधा अपने सपनों को साकार कर सकें। इसी सोच के साथ जिले में छात्रवृत्ति योजनाओं और शैक्षणिक सहायता कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया।

प्री-एसएससी स्कॉलरशिप योजना के तहत वडोदरा जिले में 22,886 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया गया, जिस पर 210.17 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इस योजना से स्कूल स्तर पर पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने का संबल मिला है। वहीं, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 993.05 लाख रुपये की ग्रांट का उपयोग किया गया, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिली।

इसके साथ ही जिले के आदर्श रेजिडेंशियल स्कूलों और सरकारी छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इन संस्थानों में रहने वाले छात्रों के आवास, भोजन और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के उन्नयन के लिए 138.95 लाख रुपये खर्च किए गए, जिससे विद्यार्थियों को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण मिल सके।

सरकार ने केवल शिक्षा तक ही सीमित न रहते हुए युवाओं के रोजगार और करियर निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए संचालित ट्रेनिंग योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी ग्रांट का पूर्ण उपयोग किया गया और 18 अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं और अन्य प्रतिष्ठित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक डॉक्टरों और वकीलों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे वे आर्थिक संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाएं। यह पहल अनुसूचित जाति वर्ग के पेशेवरों को अपने पैरों पर खड़ा होने और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो रही है।

सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के उद्देश्य से भी कई योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। कुंवरबाई मामेरू योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए 7.44 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ। डॉ. सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 90 लाख रुपये की ग्रांट का पूर्ण उपयोग किया गया, जो सामाजिक समानता और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इसके अतिरिक्त सिविल यूनिट एवं एट्रोसिटी सहायता योजनाओं के तहत 69 लाभार्थियों को कुल 39.75 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। इन योजनाओं के माध्यम से पीड़ितों को त्वरित राहत और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया गया, जिससे उनमें सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत हुई।

वडोदरा जिले में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित ये सभी योजनाएं केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास की दिशा में सरकार की स्पष्ट नीति और मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाती हैं। जिले में शिक्षा से लेकर रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तक किए जा रहे ये प्रयास आने वाले समय में अनुसूचित जाति समुदाय के जीवन स्तर में ठोस और सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद जगाते हैं।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा 31891 रुपये और चांदी वायदा में 156078 रुपये लुढ़काः क्रूड ऑयल वायदा 286 रुपये फिसला

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 30 जनवरी से 5 फरवरी के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 2370030.86 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 766390.58 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 1603582.26 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 37473 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 68436.9 करोड़ रुपये का हुआ। आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 595099.04 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 180499 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 183493 रुपये और नीचे में 137065 रुपये पर पहुंचकर, 183962 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 31891 रुपये या 17.34 फीसदी लुढ़ककर 152071 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 23355 रुपये या 15.69 फीसदी गिरकर 125512 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 3108 रुपये या 16.58 फीसदी लुढ़ककर 15638 रुपये प्रति 1 ग्राम बंद हुआ। सोना-मिनी मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 175259 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 179000 रुपये और नीचे में 131607 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 29816 रुपये या 16.55 फीसदी औंधकर 150316 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में प्रति 10 ग्राम 182600 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 185000 रुपये और नीचे में 134397 रुपये पर पहुंचकर, 184425 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 30578 रुपये या 16.58 फीसदी गिरकर 153847 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 383898 रुपये के भाव पर खूलकर, 389986 रुपये के उच्च और 225805 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 399893 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 156078 रुपये या 39.03 फीसदी की गिरावट के साथ 243815 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा सप्ताह के अंत में चांदी-मिनी फरवरी वायदा 158733 रुपये या 38.65 फीसदी घटकर 251971 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 159214 रुपये या 38.73 फीसदी गिरकर सप्ताह के अंत में 251845 रुपये प्रति किलो हुआ।

कमोडिटी वायदाओं में 766390 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 1603582 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 595099 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37473 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 69173.01 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 183.5 रुपये या 13 फीसदी औंधकर 1228 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 20.5 रुपये या 6.02 फीसदी औंधकर सप्ताह के अंत में 320.25 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 34.2 रुपये या 10.01 फीसदी घटकर 307.3 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 12 रुपये या 5.95 फीसदी की गिरावट के साथ 189.65 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 43608.60 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 5938 रुपये के भाव पर खूलकर, 6087 रुपये के उच्च और 5515 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 286 रुपये या 4.74 फीसदी लुढ़ककर 5746 रुपये प्रति बैरल बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 284 रुपये या 4.71 फीसदी गिरकर 5747 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 354.9 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 402.3 रुपये के उच्च और 286.5 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 352 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 34.7 रुपये या 9.86 फीसदी लुढ़ककर 317.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 34.4 रुपये या 9.79 फीसदी औंधकर सप्ताह के अंत में 317.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 997 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 8.6 रुपये या 0.87 फीसदी गिरकर 983.5 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 346500.61 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 248598.43 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 59318.70 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 4748.91 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 464.86 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 4640.54 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 11695.23 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 31809.50 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सप्ताह के अंत में सोना के वायदाओं में 8166 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 45628 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 15434 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 205085 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 26298 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6152 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 12768 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 31666 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 11869 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 10943 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 48300 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 51199 के उच्च और 34994 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 11860 पॉइंट घटकर 37473 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।